Drishti IAS

करेंट अफेयर्स हरियाणा

नवम्बर 2023

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

हरियाणा **4**

➢ हरियाणा में बनाई जाएगी एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 4

➢ हरियाणा पूरे देश में प्रॉपर्टी आईडी लागू करने वाला पहला राज्य 5

➢ प्रदेश के चार पुलिसकर्मी डीजीपी उत्तम सेवा पदक के लिये चयनित 6

➢ हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना 7

➢ कौशल विकास विभाग व आई.सी.आई.सी.आई. फाउंडेशन के बीच समझौता 7

➢ गृह मंत्री ने 37वें नेशनल गेम्स में पदक विजेता अंबाला के जिम्नास्टिक खिलाड़ियों को सम्मानित किया 8

➢ 37वें राष्ट्रीय खेल: हरियाणा ने एथलीट, शूटिंग और कुश्ती में जीते गोल्ड 9

➢ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया 5 नई योजनाओं का शुभारंभ 9

➢ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के रसायन विभाग के प्रो. सोहन लाल को मिला युवा वैज्ञानिक अवॉर्ड 10

➢ छात्र परिवहन सुरक्षा योजना 11

➢ ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु तैयार होगा पंचायत विकास सूचकांक 12

➢ हरियाणा सरकार ने बढ़ाया गन्ने की अगेती फसल का रेट 13

➢ हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन 14

➢ मुख्यमंत्री ने किया पिंजौर में हॉट एयर बैलून सफारी का शुभारंभ 15

➢ एन.डी.सी. पोर्टल का उन्नत संस्करण द्विभाषी विकल्पों के साथ लॉन्च 17

➢ गौशालाओं और वाटर यूजर एसोसिएशन को अनुदान पर दिये जायेंगे सोलर पंप 17

➢ हरियाणा सरकार ने लांच किया 'मिशन कर्मयोगी हरियाणा' कार्यक्रम 18

➢ मुख्यमंत्री ने हथिनी कुंड बैराज पर वॉटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का किया शुभारंभ 19

➢ फरीदाबाद में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का होगा आयोजन 20

➢ 37वाँ राष्ट्रीय खेल: हरियाणा 192 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा 22

➢ अब ज़िलास्तर पर खुलेंगे चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 डेस्क 22

नोट :

- जूनियर महिला हॉकी विश्वकप: सोनीपत की तीन महिला खिलाड़ियों का भारतीय टीम में हुआ चयन 23
- सहकारिता मंत्री ने की करनाल शुगर मिल के 48वें पिराई सत्र की शुरुआत 24
- 9वाँ भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव-2023 25
- ध्यानचंद अवार्डी सज्जन सिंह का निधन 26
- भारतीय तकनीक से सुधरेगी 34 देशों की मिट्टी-पानी की गुणवत्ता 27
- हकृवि के 10 विद्यार्थियों का पौलेंड के वारसॉ विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण के लिये हुआ चयन 28
- 'मिशन हरियाणा कर्मयोगी' के तहत नैतिक व्यवहार मुख्य प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आरंभ 28
- चालू वित्त वर्ष में हरियाणा में अब तक 1.62 लाख टन मत्स्य उत्पादन 29
- आइडियाथॉन हरियाणा 2023 का शुभारंभ 29
- आईआईटीएफ: हरियाणा मंडप में दिखी आधुनिक तकनीक से बनी ई-साइकिल 30
- दयालु योजना के तहत 1159 लाभार्थियों को दी गई 44.48 करोड़ रुपए की राशि 31
- हरियाणा सरकार निकायों के सफाई कर्मचारियों को देगी प्रोत्साहन राशि 32
- देश में सैनिक एवं अर्द्धसैनिक कल्याण विभाग गठित करने वाला हरियाणा पहला राज्य 32
- मुख्यमंत्री ने 8 राज्य राजमार्गों के सुधार और सिवाहा-पिल्लूखेड़ा रोड के चौड़ीकरण को दी मंज़ूरी 33
- बकाया राशि की वसूली के लिये 'हरियाणा एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम 2023' को मिली मंज़ूरी 35
- हरियाणा मंत्रिमंडल ने संचार और कनेक्टिविटी अवसंरचना नीति में संशोधन को दी मंज़ूरी 35
- पानीपत रिफाइनरी के विस्तार के लिये तीन गाँवों की ग्राम पंचायतों को ज़मीन बेचने की मंज़ूरी मिली 36
- राज्य की पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-ए की 7 जातियाँ हरियाणा अनुसूचित जाति वर्ग सूची में शामिल 36
- सरकार ने 32.69 करोड़ रुपए की 14 नई परियोजनाओं को दी मंज़ूरी 36
- हरियाणा एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद करने वाला बना देश का पहला राज्य 37

नोट :

हरियाणा

हरियाणा में बनाई जाएगी एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास नागरिक एवं उड्डयन विभाग का प्रभार भी है, ने चंडीगढ़ में नागरिक एवं उड्डयन विभाग के विभिन्न प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करते हुए बताया कि प्रदेश में एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई जाएगी जिससे राज्य में स्पोर्ट्स टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा।

प्रमुख बिंदु

- उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई देश की पहली 'नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी' का अध्ययन करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई जाएगी जिसमें प्रतिभागियों को अधिक से अधिक आकर्षित किया जा सके, जिससे प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी होगी।
- राज्य में एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू होने के बाद स्पोर्ट्स टूरिज्म का भी विकास होगा और युवाओं के लिये रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे।
- एयर स्पोर्ट्स के अंतर्गत एयर रेसिंग, एरोबैटिक्स, एयरोमॉडलिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैरा ग्लाइडिंग, पैरा मोटरिंग और स्काई डाइविंग जैसे कई अन्य खेल आते हैं। इन खेलों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ भी होती हैं।
- हरियाणा भी भौगोलिक क्षेत्र और अलग-अलग क्षेत्रों में साफ मौसम की स्थितियाँ एयर स्पोर्ट्स के लिये उपयुक्त है।
- एयर स्पोर्ट्स एक्टिविटी से प्रदेश सरकार को न सिर्फ सीधा रेवेन्यू आएगा बल्कि ट्रैवेल ग्रोथ, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थानीय रोज़गार में भी वृद्धि होगी। प्रदेश सरकार की कोशिश है कि अन्य खेलों की तरह हरियाणा राज्य एयर स्पोर्ट्स हब बने।
- विदित हो कि भारत अभी ऐसी किसी प्रतियोगिता में स्थायी तौर पर हिस्सा नहीं लेता लेकिन केंद्र सरकार की इस पहली बार बनी नई नीति के कारण जल्द ही भारत इन खेलों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शामिल हो सकता है। भारत में युवाओं की एक बड़ी संख्या है जिनका रुझान रोमांचक खेलों और उड़ान संबंधी खेलों में बढ़ रहा है।

नोट :

हरियाणा पूरे देश में प्रॉपर्टी आईडी लागू करने वाला पहला राज्य

चर्चा में क्यों ?

31 अक्तूबर, 2023 को हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने पत्रकारवार्ता में कहा कि हरियाणा पूरे देश में प्रॉपर्टी आईडी लागू करने वाला पहला राज्य है।

प्रमुख बिंदु

- डॉ. कमल गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की 'क्रीएशन ऑफ न्यू प्रॉपर्टी-आईडी अंडर नॉर्मल एंड तत्काल स्कीम' की सराहना की और इसे अन्य राज्यों को अपनाने का सुझाव भी दिया।
- डॉ. गुप्ता ने प्रॉपर्टी आईडी के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि लाल डोरे के अंदर आने वाली 34 लाख प्रॉपर्टीज़ को इंटिग्रेट कर नई प्रॉपर्टी आईडी में सम्मिलित किया गया और नई प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई है। अब रजिस्ट्री ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी आईडी डाटा में चढ़ाई जा सकती है।
- उन्होंने कहा कि अब तक 2274 अनधिकृत कॉलोनियों में से 494 को अधिकृत कर दिया गया है तथा अन्य पर कार्य चल रहा है। 31 जनवरी, 2024 तक लगभग 850 कॉलोनियों को अधिकृत कर दिया जाएगा।
- डॉ. गुप्ता ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत 31 दिसंबर, 2020 को 20 वर्ष पूरे होने वाले दुकानदारों को मालिकाना हक दिलाने का कार्य भी शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने किया है।
- मंत्री ने बताया कि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी सूचना एसएमएस के माध्यम से शहरी स्थानीय निकाय के नागरिकों को भेज सकते हैं।
- डॉ. गुप्ता ने कहा कि वर्ष 2023-24 के प्रॉपर्टी टैक्स की पूर्ण अदायगी करने पर सीमित समय के लिये छूट दी है, जो छूट 15 नवंबर, 2023 तक जारी रहेगी। अब प्रॉपर्टीधारक किसी भी प्रकार की त्रुटि के निवारण हेतु विभागीय पोर्टल पर स्वयं भी अपनी प्रॉपर्टी का डाटा सत्यापित कर सकते हैं।

1.80 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वर्ग के परिवारों को आयुष्मान/चिरायु योजना का लाभ मिलना शुरू

चर्चा में क्यों ?

1 नवंबर, 2023 को हरियाणा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय परिवारों को बड़ी सौगात देते हुए 1.80 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वर्ग के परिवारों के सदस्यों को सैद्धांतिक रूप से कार्ड वितरित कर आयुष्मान/ चिरायु योजना का लाभ देने की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

- विदित हो कि आयुष्मान/चिरायु योजना के तहत अभी तक 38,000 परिवारों ने आवेदन किया था। हरियाणा दिवस से इन सभी परिवारों को आयुष्मान/चिरायु योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया।
- बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के कर्मचारी व पेंशन भोगियों को भी तोहफा देते हुए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का भी शुभारंभ किया।
- प्रथम चरण में दो विभाग नामत: मत्स्य व बागवानी के 894 कर्मचारियों को इसमें शामिल किया गया है और प्रथम चरण में बीमारियों के 1055 पैकेज व हरियाणा के 305 अस्पतालों को सम्मिलित किया गया है।
- आगामी समय में अन्य विभागों में भी इस कैशलेस सुविधा को लागू कर दिया जाएगा, जिससे प्रदेश के सभी कर्मचारियों को लाभ होगा। इसके अलावा, प्रदेश के मान्यताप्राप्त पत्रकार भी कैशलेस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
- इस सुविधा के पूरी तरह लागू होने पर हरियाणा के करीब 3.5 लाख नियमित कर्मचारी, 3 लाख पेंशनभोगी और उनके 20 लाख आश्रित सूचीबद्ध अस्पतालों में नकद रहित (कैशलेस) उपचार की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

नोट :

- मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में कुल 1340 बीमारियों को कवर किया गया है। प्रदेश में सूचीबद्ध 569 अस्पतालों में इस कैशलेस सुविधा का लाभ उठाया जा सकेगा व भविष्य में देशभर के अस्पताल इस योजना से जोड़े जाएंगे।

प्रदेश के चार पुलिसकर्मी डीजीपी उत्तम सेवा पदक के लिये चयनित

चर्चा में क्यों ?

31 अक्तूबर, 2023 को पुलिस विभाग द्वारा डीजीपी उत्तम सेवा पदक के लिये प्रदेश में चार पुलिसकर्मियों का तथा नकद पुरस्कार के लिये एक अन्य पुलिसकर्मी का नाम चयनित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पुलिसकर्मियों के उत्साहवर्धन के लिये तीन प्रकार के राज्यस्तरीय अवॉर्ड मंज़ूर किये गए हैं, जिनमें मुख्यमंत्री वीरता पदक, गृह मंत्री उत्कृष्ट अन्वेषण पदक तथा डीजीपी उत्तम सेवा पदक शामिल हैं।
- मुख्यमंत्री वीरता पदक विजेता को ईनामस्वरूप 2 लाख रुपए, गृह मंत्री उत्कृष्ट अन्वेषण पदक विजेता को एक लाख रुपए तथा डीजीपी उत्तम सेवा पदक विजेता को 50 हज़ार रुपए की राशि से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा, अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र/स्क्राल भी मिलेगा।
- डीजीपी उत्तम सेवा पदक विजेता के तहत हरियाणा प्रदेश में 4 पुलिसकर्मियों का चयन किया गया है, जिन्हें 50 हज़ार रुपए की राशि से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही एक अन्य पुलिसकर्मी को 10 हज़ार रूपए की नकद राशि से सम्मानित किया जाएगा।
- डीजीपी उत्तम सेवा पदक के लिये चयनित पुलिसकर्मियों में सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार, हेड कॉन्स्टेबल अंकुश, इंस्पेक्टर राम कुमार और सब-इंस्पेक्टर अजब सिंह शामिल है। वहीं सब-इंस्पेक्टर शमशेर सिंह को 10 हज़ार रुपए की नकद राशि से सम्मानित किया जाएगा।
- आईजी ट्रैफिक एंड हाईवे करनाल कार्यालय में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत् प्रदीप कुमार ने अपनी ड्यूटी के दौरान यातायात व्यवस्था संबंधी अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य किये। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में यातायात को लेकर आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं के सुचारु संचालन में भी महत्त्वपूर्ण सहयोग दिया।
- हेड कॉन्स्टेबल अंकुश को साइबर सेल में अपनी उत्कृष्ट सेवाएँ देने के लिये सम्मानित किया जा रहा है। अंकुश द्वारा साइबर सुरक्षा को लेकर बनाई जाने वाली कार्य योजना के बेहतर क्रियान्वयन में उदाहरणात्मक प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही अंकुश ने 1600 से अधिक अध्यापकों तथा विद्यार्थियों और 1250 से अधिक पुलिस कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण दिया।
- वर्तमान में हिसार ज़िला में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत् राम कुमार ने अपने कार्यकाल में कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ काम करते हुए कई गंभीर मामलों को सुलझाने में अपना सहयोग दिया। उनकी मेहनत व लगन के चलते इन्हें इंस्पेक्टर के पद पर भी पदोन्नति दी गई।

- ज़िला पंचकूला में कार्यरत् सब-इंस्पेक्टर अजब सिंह सदैव अपनी ड्यूटी को लेकर काफी मेहनती तथा समर्पित रहे, जिसके चलते इन्हें पुलिस विभाग में वर्ष 2017 में पदोन्नत भी किया गया। ड्यूटी के दौरान इनकी कार्य प्रणाली बहुत ही व्यवस्थित तथा निष्पक्ष रही।
- वर्तमान में हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुबन में सब-इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत् शमशेर सिंह ने अपनी ड्यूटी के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल स्थापित करते हुए कई मामलों में अच्छा प्रदर्शन किया। जिसके चलते इन्हें ईनाम स्वरूप 10 हज़ार रुपए की नकद राशि भेंट की जाएगी।

हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना

चर्चा में क्यों ?

3 नवंबर, 2023 को हरियाणा महिला विकास निगम के प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिये हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से वर्ष 2021-22 से 'हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना'शुरू की है।

प्रमुख बिंदु

- प्रवक्ता ने बताया कि महिलाओं के उत्थान तथा उन्हें अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिये निगम सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, ताकि वे कृषि, उद्योग, व्यापार जैसे क्षेत्रों में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।
- योजना के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से हरियाणा की स्थायी निवासी महिलाओं/लड़कियों, जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपए से अधिक न हो तथा आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो, को बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का ऋण दिलवाया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत प्रार्थी द्वारा समय पर किस्तों का भुगतान करने पर 3 वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि निगम द्वारा दी जाती है।
- प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत विभिन्न क्रियाकलापों जैसे कि ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के लिये वाहन, थ्री व्हीलर, टैक्सी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोकॉपी की दुकान, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, हैंडलूम, बैग बनाना, कैंटीन सर्विस इत्यादि के लिये महिलाओं को ऋण प्रदान करवाया जाता है।

कौशल विकास विभाग व आई.सी.आई.सी.आई. फाउंडेशन के बीच समझौता

चर्चा में क्यों ?

3 नवंबर, 2023 को प्रदेश में बेरोज़गार युवाओं को रोज़गारपरक बनाने की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग व आई.सी.आई.सी.आई. फाउंडेशन के मध्य एक 'समझौता ज्ञापन'पर हस्ताक्षर हुये।

प्रमुख बिंदु

- कौशल विभाग के महानिदेशक डॉ. विवेक अग्रवाल ने बताया कि इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत आई.सी.आई.सी.आई. फाउंडेशन बाबू मूल चंद जैन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, करनाल के प्रांगण में कंप्यूटर लैब स्थापित करेगा।

- इसके तहत राज्य में बेरोज़गार युवाओं को रोज़गारपरक बनाने के लिये आई.टी.आई. के प्रशिक्षणार्थियों को सॉफ्ट स्किल, साक्षात्कार कौशल, टीम वर्क, नेतृत्व, समय प्रबंधन, समस्या समाधान, भावनात्मक सक्षमता इत्यादि के बारे में प्रशिक्षण करवाने हेतु प्रत्येक तीन मास में एक वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा।
- डॉ. विवेक अग्रवाल ने यह भी बताया कि आई.सी.आई.सी.आई. फाउंडेशन के साथ विभाग द्वारा इस आशय-पत्र पर भी हस्ताक्षर किये गए, जिसके अंतर्गत आई.सी.आई.सी.आई. फाउंडेशन 5 विभिन्न राजकीय आई.टी.आई. में कंप्यूटर लैब स्थापित करेगा, जिसके माध्यम से आई.टी.आई. के प्रशिक्षणार्थियों को कंप्यूटर पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

गृह मंत्री ने 37वें नेशनल गेम्स में पदक विजेता अंबाला के जिम्नास्टिक खिलाड़ियों को सम्मानित किया

चर्चा में क्यों?

3 नवंबर, 2023 को हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी के वार हीरोज़ मेमोरियल स्टेडियम के जिम्नास्टिक हाल में 37वें नेशनल गेम्स में जिम्नास्टिक के पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- नेशनल गेम्स जिम्नास्टिक में अंबाला के योगेश्वर सिंह ने तीन स्वर्ण पदक व दो कांस्य पदक तथा साहिल यादव व रोहित कुमार ने एक-एक कांस्य पदक जीता था। इन सभी खिलाड़ियों को गृह मंत्री अनिल विज ने सम्मानित करते हुए योगेश्वर सिंह को एक लाख एवं अन्य दो खिलाड़ियों को 50-50 हज़ार रुपए अपने स्वैच्छिक कोष से देने की घोषणा की।
- इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा की खेल नीति सारे देश में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और दूसरे राज्य भी इसका अनुसरण कर रहे हैं। हरियाणा में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है और इसके साथ-साथ नौकरी दिये जाने का भी प्रावधान है।
- गृह मंत्री ने कहा कि अंबाला छावनी, जोकि फुटबॉल का गढ़ था, इसके दृष्टिगत यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फीफा से अप्रूव्ड फुटबॉल खेल स्टेडियम बनाया गया है। आल वेदर स्वीमिंग पूल, आधुनिक सुविधाओं से युक्त जिम्नास्टिक हाल खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाया गया है।

37वें राष्ट्रीय खेल: हरियाणा ने एथलीट, शूटिंग और कुश्ती में जीते गोल्ड

चर्चा में क्यों ?

3 नवंबर, 2023 को गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में शूटिंग के पहले ही दिन हरियाणा ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते, वहीं एथलीट और कुश्ती में भी खिलाड़ियों ने प्रदेश को अनेक पदक दिलाये।

प्रमुख बिंदु

- शूटिंग के पहले दिन हुए मुकाबले में सागर भार्गव ने प्रदेश के लिये गोल्ड मेडल जीता, जबकि ओलंपिक का कोटा प्राप्त कर चुके सरबजोत सिंह ने सिल्वर मेडल जीता।
- राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा की गतका टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। गतका टीम के खिलाड़ी जसविंदर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि सुनिधि चौहान पहले ही ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी थीं।
- हरियाणा सेपक टाकरा महिला टीम ने प्रदेश की झोली में सिल्वर मेडल डाला। हरियाणा की हॉकी की महिला टीम ने ओडिशा को 7-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। वहीं हरियाणा तीरंदाज़ी की तीनों टीमें फाइनल में पहुँच गई हैं।
- राष्ट्रीय खेलों के कुश्ती के मुकाबले में 97 किलोग्राम भार वर्ग में नितेश ने गोल्ड, 77 किलोग्राम भार वर्ग में विकास ने और 68 किलोग्राम भार वर्ग में आरज़ू ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि 125 किलोग्राम भार वर्ग में सुमित मलिक ने प्रदेश को सिल्वर मेडल दिलाया।
- इनके अलावा 97 किलोग्राम भार वर्ग में रोहित बूरा ने, 86 किलोग्राम भार वर्ग में राकेश ने, 76 किलोग्राम भार वर्ग में दीपक पूनिया ने, 68 किलोग्राम भार वर्ग में स्वाति बेरवाल ने, 50 किलोग्राम भार वर्ग में स्वीटी ने प्रदेश के लिये ब्रॉन्ज मेडल जीते।
- जैवलिन थ्रो में शिल्पा रानी ने गोल्ड मेडल व प्रियंका सिंह ने सिल्वर मेडल, शॉट पुट में मनप्रीत ने सिल्वर मेडल, 400 मीटर की रेस में विक्रम पंचाल ने सिल्वर मेडल, हैमर थ्रो में अजय ने सिल्वर मेडल व हेमथोलोन में तनु ने प्रदेश को सिल्वर मेडल दिलाया। 20 किलोमीटर की पैदल चाल में हरदीप ने ब्रॉन्ज मेडल तथा 800 मीटर की रेस में पूजा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया 5 नई योजनाओं का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

2 नवंबर, 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में अंत्योदय उत्थान के लिये हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गईं 5 नई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ज़िला करनाल में आयोजित अंत्योदय महासम्मेलन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने इन 5 योजनाओं- आयुष्मान भारत चिरायु योजना, हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड, मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (HAPPY) और मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना का शुभारंभ किया।
- आयुष्मान भारत-चिरायु योजना
  - केंद्रीय गृह मंत्री ने इस योजना में राज्य के 14 लाख नए परिवारों को जोड़ा है। अब केंद्र एवं राज्य सरकार की योजना को मिलाकर हरियाणा के लगभग 40 लाख अंत्योदय परिवार आयुष्मान भारत-चिरायु योजना का लाभ उठा सकेंगे।
  - इसके अतिरिक्त 1.80 लाख से 3 लाख रुपए वार्षिक आय वाले लगभग 38 हज़ार परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया गया है।
  - विदित हो कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हरियाणा के 15 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का वार्षिक इलाज मुफ्त मिलता है। साथ ही हरियाणा सरकार की चिरायु योजना से अब तक लगभग 11 लाख परिवारों को यह लाभ मिल रहा है।
- हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड
  - केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में अंत्योदय परिवारों की आय बढ़ाने के लिये हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड का शुभारंभ किया।

- यह बोर्ड अंत्योदय परिवारों के लिये अभी तक राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की निगरानी व समीक्षा करेगा। साथ ही, यह बोर्ड आय जल्दी से बढ़ाने के लिये नई योजनाएँ भी बनाएगा और उनका कार्यान्वयन भी सुनिश्चित करेगा।

- हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हैप्पी)
  - केंद्रीय गृह मंत्री ने हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हैप्पी) का शुभारंभ किया।
  - इस योजना के तहत सालाना 1 लाख रुपए से कम आय वाले अंत्योदय परिवारों, जिनके 3 से अधिक सदस्य हैं, के हर सदस्य को हरियाणा रोडवेज की बसों में प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर तक नि:शुल्क यात्रा करने की सुविधा दी जाएगी।
- मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना
  - केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना का भी शुभारंभ किया। इस योजना में उन अंत्योदय परिवारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो ऋण लेकर मिनी डेयरी खोलना चाहते हैं।
  - ऐसे परिवार जब मिल्क यूनियन में दूध बेचेंगे तो उन्हें एक साल तक दूध पर सहकारिता यूनियन के मूल्य से प्रति लीटर 10 रुपए ज़्यादा दिये जाएंगे।
- मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना
  - केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का भी शुभारंभ किया।
  - इस योजना में 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के 60 साल से अधिक आयु के सदस्यों को अयोध्या, वाराणसी आदि तीर्थों के दर्शन करवाए जाएंगे। आने-जाने का सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के रसायन विभाग के प्रो. सोहन लाल को मिला युवा वैज्ञानिक अवॉर्ड

चर्चा में क्यों ?

6 नवंबर, 2023 को दिल्ली में गलगोटियास विश्वविद्यालय में पर्यावरण एवं सामाजिक विकास संघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के कुरुक्षेत्र ज़िले में स्थित कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के रसायन विभाग के प्रो. सोहन लाल को युवा वैज्ञानिक अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि युवा वैज्ञानिक अवॉर्ड शोध के क्षेत्र में कार्य करने वाले 40 साल से कम उम्र के शोधार्थियों को दिया जाता है। प्रो. सोहन कुमार को 37 साल की उम्र में शोध के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिये अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है।
- यह अवॉर्ड युवाओं को शोध के क्षेत्र में और पर्यावरण संरक्षण को लेकर उत्कृष्ट कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करता है और साथ ही और मेहनत करने के लिये प्रेरित भी करता है।
- प्रो. सोहन लाल ने पर्यावरण को दूषित करने में बढ़ रही गंभीर समस्या अपशिष्ट पॉलिथीन को पुन: प्रयोग में लाने के लिये शोध के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है।
- इन्होंने शोध किया है कि अपशिष्ट पॉलिथीन के पुन: प्रयोग से पेवर ब्लॉक, कुर्सी या अन्य प्रयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है, जिससे प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण भी कम होगा और उसे दोबारा से प्रयोग में भी लाया जा सकेगा।
- इन्होंने अपशिष्ट पॉलीथिन को प्रयोग में लाने के लिये काम किया है तो वहीं प्राकृतिक अवयवों युक्त एंटीबायोटिक दवा बनाने का भी कार्य किया है और निरंतर शोध के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।
- प्रो. सोहन लाल को यह अवॉर्ड चिपको आंदोलन की शुरुआत करने वाले पद्म भूषण चंडीप्रसाद भट्ट के हाथों मिला है, जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है।

छात्र परिवहन सुरक्षा योजना

चर्चा में क्यों?

5 नवंबर, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल ज़िले के गाँव रतनगढ़ में जनसंवाद कार्यक्रम में 'छात्र परिवहन सुरक्षा योजना' के शुरू करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- 'छात्र परिवहन सुरक्षा योजना' के तहत गाँव में 50 से अधिक विद्यार्थी होने पर दूर-दराज के स्कूल में जाने के लिये अब परिवहन विभाग की ओर से बस सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- रतनगढ़ गाँव में सुबह 7 बजे रोडवेज विभाग की बस विद्यार्थियों का इंतजार करेगी। यह बस विद्यार्थियों को स्कूल ले जाने और फिर घर छोड़ने का काम करेगी।

नोट :

- जिस गाँव में 30 से 40 विद्यार्थी हैं वहाँ पर मिनी बस, जिस गाँव में 5 से 10 विद्यार्थी हैं वहाँ पर ऑटो रिक्शा जैसी सुविधा मिलेगी। यह सुविधा विद्यार्थियों को नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। इसका पैसा ज़िला शिक्षा विभाग के माध्यम से खर्च किया जाएगा।
- इस योजना को प्रथम चरण में करनाल ज़िला और उसके बाद प्रदेश के अन्य ज़िलों में लागू की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु तैयार होगा पंचायत विकास सूचकांक

चर्चा में क्यों ?

6 नवंबर, 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में आयोजित बैठक में बताया कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास करने के लिये विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा पंचायत विकास सूचकांक तैयार किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पंचायत विकास सूचकांक इसलिये तैयार किया जा रहा है ताकि चहुमुंखी विकास की योजनाओं के साथ सतत विकास का लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सके।
- मुख्य सचिव ने कहा कि 12 बड़े विभागों की 57 सेवाओं के लिये डाटा एकत्र किया जाएगा, जिस पर बेहतर विकास योजनाएँ तैयार की जाएगी।
- यह पंचायत विकास सूचकांक सामाजिक, आर्थिक पैरामीटर और सूचकांक के आधार पर स्थानीय समुदाय के विकास स्थिति को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा।
- इसमें बहुत से कार्यक्षेत्र व सैक्ट्रल सूचकांक का उपयोग किया जाएगा, जिसमें बिजली, पानी, सड़कें, सफाई सुविधाओं, इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाएँ, संस्थान, साक्षरता एवं गरीबी रेट सहित आर्थिक एवं सामाजिक सूचकांक, गवर्नेंस एवं प्रशासन, पर्यावरणीय स्थिरता को शामिल किया गया है।
- विकास सूचकांक में ग्रामीण समुदायों में असमानताओं की पहचान करना, स्थाई विकास, लक्ष्य की उपलब्धियाँ और उनके बेहतर जीवन के लिये नीतियों का लक्ष्य तैयार किया जाएगा।
- इसमें गरीबी मुक्त और आजीविका गाँवों में बढोतरी, स्वस्थ गाँव, बच्चों की हितकारी पंचायतें, पर्याप्त जल, साफ एवं हरियाली युक्त पंचायतें, बुनियादी ढाँचे के साथ आत्मनिर्भर पंचायतें, सामाजिक न्याय एवं सुरक्षित पंचायतें, सुशासन एवं महिला हितैषी पंचायतों के साथ समग्र विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।

- इसके लिये स्टेट स्टीयरिंग कमेटी एवं ज़िला व ब्लॉक स्टीयरिंग तथा सत्यापन कमेटियों का गठन किया जा चुका है। ये कमेटियाँ पंचायतों की ग्रेडिंग कर गुणवत्तायुक्त डाटा तैयार करेंगी और पंचायत स्तर पर योजना बनाकर उसकी समीक्षा भी करेंगी।
- इस प्रकार हर पंचायत का डाटा रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। पंचायत स्तर पर डाटा तैयार कर पंचायत विकास सूचकांक पोर्टल pdi.gov.in पर 31 दिसंबर, 2023 तक अपलोड किया जाएगा।
- ज़िला डाटा सत्यापन टीम के चेयरमैन संबंधित ज़िलों के उपायुक्त होंगे तथा ज़िला परिषद के सीईओ सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा 12 अन्य ज़िला स्तरीय विभागों के मुखिया को सदस्य बनाया गया है, जो 577 स्थानीय सूचकांक पर कार्य करेंगे।
- विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक ने बताया कि राज्य में 10 गाँवों की पंचायतों का डाटा एकत्र करने के लिये रिहर्सल की जा चुकी है। जल्द ही सभी पंचायतों का डाटा एकत्र किया जाएगा।

हरियाणा सरकार ने बढ़ाया गन्ने की अगेती फसल का रेट

चर्चा में क्यों ?

6 नवंबर, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों को दिवाली का तोहफा देते हुए गन्ने के मूल्य में अगेती किस्म के लिये बढ़ोतरी की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस वर्ष के लिये गन्ने का मूल्य अगेती किस्म के लिये 372 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 386 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया जाता है, जोकि 14 रुपए की पर्याप्त वृद्धि है।
- इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने अगले साल के लिये भी गन्ने के रेट में बढ़ोतरी की घोषणा की है। अगले वर्ष जिन दिनों गन्ने का रेट घोषित होता है, उन दिनों में आचार संहिता लगी होगी। इसलिये विभाग से परामर्श करके अगले वर्ष के लिये गन्ने का रेट 400 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया जाता है।

- सरकार द्वारा लिये गए इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गन्ना किसानों को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिये उचित मूल्य मिले।
- मुख्यमंत्री ने गन्ने की दरों में उल्लेखनीय वृद्धि करके गन्ना किसानों को प्रोत्साहित किया है और उनके इस कदम से गन्ना किसानों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने और हरियाणा के कृषि क्षेत्र की समृद्धि में योगदान होने की उम्मीद है।
- विदित हो कि हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है, जहाँ 14 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जाती है।

हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन

चर्चा में क्यों?

6 नवंबर, 2023 को हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार ने व्यापारियों के कल्याण के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराते हुए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन किया है।

प्रमुख बिंदु

- इसका मुख्य उद्देश्य व्यापारियों की समस्याओं व मुद्दों का समाधान करना, व्यापारी व राज्य सरकार के बीच एक सेतु का काम करना, व्यापारियों की सामाजिक सुरक्षा व बीमा कवर सुनिश्चित करना है।
- इसके अलावा, राज्य में निवेश व रोज़गार के अवसर बढ़ाना, व्यापारियों से जुड़े विभिन्न विभागों के नियमों व शर्तों का विश्लेषण करना और उनके समीकरण के लिये सरकार को सुझाव देने के साथ-साथ व्यापारिक कल्याण फंड का गठन करना भी इसका उद्देश्य है।
- अधिसूचना के अनुसार बोर्ड में 18 वर्ष से अधिक आयु का एक व्यक्ति चेयरमैन तथा दो व्यक्ति वाईस चेयरमैन होंगे।
- इसके अलावा वित्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, श्रम, आबकारी व कराधान, उद्योग एवं वाणिज्य, ऊर्जा, खनन एवं भूविज्ञान, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभागों के प्रशासनिक सचिव बोर्ड के सदस्य होंगे जबकि हरियाणा सिविल सेवा का अधिकारी जो बोर्ड का सचिव भी है, सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा।
- अधिसूचना अनुसार राज्य सरकार समय-समय पर दस गैर-सरकारी सदस्यों को बोर्ड का सदस्य भी मनोनीत कर सकती है।
- बोर्ड का मुख्यालय चंडीगढ़/पंचकूला में होगा। यदि आवश्यक हो तो चेयरमैन राज्य में कहीं भी बैठक बुला सकता है।

नोट :

मुख्यमंत्री ने किया पिंजौर में हॉट एयर बैलून सफारी का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

8 नवंबर, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के पंचकूला ज़िले में स्थित 'गेट वे ऑफ हिमाचल' कहे जाने वाले पिंजौर में हॉट एयर बैलून सफारी का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वयं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता और स्कूल शिक्षा और विरासत एवं पर्यटन मंत्री कंवर पाल के साथ सबसे पहले हॉट एयर बैलून सफारी की सवारी की।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हॉट एयर बैलून सफारी सुरक्षा की दृष्टि से काफी सुरक्षित है। हॉट एयर बैलून संचालित करने वाली कंपनी ने सुरक्षा सर्टिफिकेट प्राप्त किये हुए हैं।
- हॉट एयर बैलून सफारी का आनंद उठाने के लिये 13 हज़ार रुपए प्रति सवारी प्रति राइड का खर्चा आएगा। इसमें वही लोग सवारी कर पाएंगे जो स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों को पूरा करेंगे। राज्य सरकार कंपनी को दो साल के लिये वीजीएफ के तौर पर 72 लाख रुपए देगी।
- इस क्षेत्र में हॉट एयर बैलून सफारी की शुरुआत होने से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इससे एक ओर जहाँ पर्यटकों को पहले से चल रही पर्यटन की गतिविधियों के अलावा उनकी यात्रा में नया अनुभव साझा करने को मिलेगा तो वहीं पिंजौर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी अवगत हो सकेंगे।
- मुख्यमंत्री ने शिवालिक पर्वत श्रृंखला में स्थित पंचकूला को साहसिक खेल गतिविधियों का केंद्र बनाया है। प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी भी पंचकूला में ही स्थित है। मोरनी हिल्स के पास टिक्करताल क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जेट स्कूटर, पैरा सेलिंग और ट्रेकिंग जैसे एडवेंचर खेलों की शुरुआत करने के बाद अब पिंजौर को भी पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिवालिक पर्वत क्षेत्र के साथ-साथ अरावली क्षेत्र को भी पर्यटन के रूप विकसित कर रही है। राज्य सरकार द्वारा अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाले गुरुग्राम और नूंह ज़िलों की 10,000 एकड़ भूमि पर दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया जा रहा है। इससे अरावली पर्वत श्रृंखला को संरक्षित करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम और नूंह क्षेत्रों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
- विदित हो कि देवभूमि हिमाचल का गेट-वे माने जाने वाले पिंजौर का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, इसे महाभारत कालीन स्थल भी माना जाता है। यह स्थल अपने भीतर हज़ारों वर्ष पुराने प्राचीन इतिहास को संजोए हुए है। यहाँ जगह-जगह प्राचीन इतिहास के अवशेष विद्यमान हैं।

- ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान अज्ञातवास का एक बड़ा समय यहां बिताया था, जिसके प्रमाण आज भी पिंजौर में देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, यहां स्थित यादविंद्रा गार्डन, जिसे पिंजौर गार्डन भी कहा जाता है, जो बेहद प्रसिद्ध है। यह मुगल गार्डन शैली का एक उदाहरण है।

नोट :

एन.डी.सी. पोर्टल का उन्नत संस्करण द्विभाषी विकल्पों के साथ लॉन्च

चर्चा में क्यों?

7 नवंबर, 2023 को हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने एन.डी.सी. पोर्टल का उन्नत संस्करण लॉन्च किया। पोर्टल अब नागरिकों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा।

प्रमुख बिंदु

- शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिये 791.44 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसके अलावा 'दिव्य नगर योजना' के तहत 50 करोड़ रुपए और 'अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन' (अमृत) योजना के तहत 3,116 करोड़ रुपए के बजट को मंज़ूरी दी गई है।
- डॉ. गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 93.66 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की गई है, जो शहरी बुनियादी ढाँचे में सुधार के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है।
- इसके अलावा, विभाग ने राज्य में पार्किंग को सुव्यवस्थित करने के लिये कदम उठाए हैं, अब तक चार-पहिया वाहनों के लिये 28,000 और दो-पहिया वाहनों के लिये 14,423 पार्किंग स्थान चिह्नित किये गए हैं। इसके अलावा, 280 किलोमीटर लंबी सड़क पर 9,141 तिरंगी लाइटें लगाई गई हैं।

गौशालाओं और वाटर यूजर एसोसिएशन को अनुदान पर दिये जायेंगे सोलर पंप

चर्चा में क्यों?

7 नवंबर, 2023 को हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश की गौशालाओं और वाटर यूजर एसोसिएशन को भी सोलर पंप अनुदान पर दिये जायेंगे। इसके लिये 14 नवंबर, 2023 तक आवेदन किया जा सकता है।

प्रमुख बिंदु

- प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का उपयोग कर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई के लिये 3 एच.पी. से 10 एच.पी. तक के सौर ऊर्जा पंप पर 75 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
- उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा अब तक 64,902 सौर ऊर्जा पंप लगाए जा चुके हैं और 26,798 पंपों की स्थापना का कार्य चल रहा है। इस योजना को क्रियान्वित करने में हरियाणा देश में द्वितीय स्थान पर है तथा विभाग द्वारा वित वर्ष 2023-24 में 70,000 पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
- प्रवक्ता ने बताया कि 1 एच.पी. से 10 एच.पी. तक के वर्ष 2019-2021 के लंबित इलैक्ट्रिक ट्यूबवेल कनेक्शन भी सोलर पर दिये जाएंगें। इसके अलावा गौशालाओं और वाटर यूजर एसोसिएशन, सामूहिक सिंचाई सिस्टम को भी सिंचाई के लिये 75 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिये जांएगे।
- इस चरण में इच्छुक किसानों से 7 नवंबर, 2023 तक saralharyana.gov.in पोर्टल पर आवेदन मांगे गए थे, जिसकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 14 नवंबर, 2023 कर दी गई है।

हरियाणा सरकार ने लांच किया 'मिशन कर्मयोगी हरियाणा' कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

7 नवंबर, 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने 'मिशन कर्मयोगी हरियाणा' (एमकेएच) कार्यक्रम लॉन्च किया। यह राज्य सरकार की 3 लाख से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक अभूतपूर्व पहल है।

प्रमुख बिंदु

- 'मिशन कर्मयोगी हरियाणा'कार्यक्रम से राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों और हितधारकों को शासन में नैतिक व्यवहार, मूल्यों और सिद्धांतों के महत्व पर ज़ोर दिया जाएगा।
- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा संचालित इस पहल का उद्देश्य नैतिक शासन को विकसित करना और सरकारी कर्मचारियों के कौशल और दक्षताओं को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य हरियाणा के नागरिकों को ठोस लाभ पहुँचाते हुए सार्वजनिक सेवा वितरण और जवाबदेही को बढ़ाना है।
- मुख्य सचिव संजीव कौशल ने प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों से 'मिशन कर्मयोगी हरियाणा' कार्यक्रम के तहत हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा) में आयोजित प्रशिक्षण सत्रों में नियमित रूप से आने का आग्रह किया।
- उन्होंने सुशासन पुरस्कारों के लिये उम्मीदवारों को नामांकित करते समय युवा अधिकारियों द्वारा राज्य की प्रमुख योजनाओं और ज़िला-स्तरीय संकेतक क्षेत्र को लागू करने में दिये गए असाधारण योगदान पर विचार करने का भी आह्वान किया।
- हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (एचआईपीए) की महानिदेशक चंद्रलेखा मुखर्जी ने बताया कि एमकेएच कार्यक्रम हब-एंड-स्पोक मॉडल को अपनाएगा। हरियाणा सरकार के अनुभवी अधिकारियों से मास्टर ट्रेनर के रूप में काम लिया जाएगा। पहले ये मास्टर ट्रेनर खुद हिपा, हरियाणा पुलिस अकादमी और डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर पंचकूला में गहन प्रशिक्षण से गुजरेंगे।

मुख्यमंत्री ने हथिनी कुंड बैराज पर वॉटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

8 नवंबर, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा यमुनानगर ज़िले में यमुना नदी पर स्थित हथिनी कुंड बैराज पर वॉटर राईडिंग व यमुना में बोटिंग की शुरुआत की गई है।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन के नाते हरियाणा में बहुत से क्षेत्रों में ऐसी गतिविधियों को बढ़ाया जा सकता है। पर्यटन के नाते कलेसर से कालका तक पहाड़ी के नीचे-नीचे बहुत सी संभावना है, जैसे कि पैदल ट्रैकिंग, साइकिल ट्रैकिंग व मोटरसाइकिल इत्यादि के माध्यम से विभिन्न स्थानों जैसे आदि बद्री, लोहगढ़, त्रिलोकपुर देवी का मंदिर का भ्रमण कर सकते हैं।
- हरियाणा में भी पर्यटन के नाते लोगों का रुझान बढ़ाने के लिये हथिनी कुंड बैराज पर पार्क भी बनाया जा रहा है। इस पार्क का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है।
- गौरतलब है कि गुरुग्राम और नूहं ज़िलों के क्षेत्र में करीब 10 हजार एकड़ मे जंगल सफारी प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। इसकी शीघ्र शुरुआत की जाएगी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि ताजे वाला हैड पहले छोटा था। उसके बाद हथिनी कुंड बैराज बनाया गया, परंतु पानी की अधिकता के कारण कलेसर में 50 मीटर ऊँचा डैम बनाया जाएगा। इस डैम से हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
- यह प्रोजेक्ट 4 प्रदेशों का मिलन बिंदु हैं। यहाँ पर पर्यटन की संभावना होगी और चारों प्रदेशों में पानी की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। इसके माध्यम से बिजली भी बना सकते हैं। इसका लाभ राजस्थान, दिल्ली को भी मिल सकेगा।

फरीदाबाद में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का होगा आयोजन

चर्चा में क्यों?

8 नवंबर, 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रूचि बढाने के लिये 17 से 20 जनवरी, 2024 तक को क्षेत्रीय जैव-प्रौद्योगिकी केंद्र फरीदाबाद में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में देशभर के विभिन्न स्कूलों एवं कालेजों के लगभग 12 हज़ार विद्यार्थी भाग लेंगे।
- अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय शोध एवं उन्नति पर विस्तार से चर्चा होगी।
- अमृतकाल के दौरान नव भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अभिनवता के क्षेत्र में नवीनतम विकास विज्ञान गतिविधियों को दर्शाया जाएगा।
- लगातार चार दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में विभिन्न वैज्ञानिक विषयों पर व्याख्यान के अलावा प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इसमें हरियाणा के कक्षा 8 से 11वीं के हर ज़िले से 35 विद्यार्थी विज्ञान पर अपने मॉडल प्रदर्शित करेंगे।

INDIA INTERNATIONAL SCIENCE FESTIVAL

नोट :

37वाँ राष्ट्रीय खेलः हरियाणा 192 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा

चर्चा में क्यों ?

9 नवंबर, 2023 को गोवा में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा 62 स्वर्ण, 55 रजत और 75 कांस्य सहित 192 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

प्रमुख बिंदु

- 26 अक्तूबर से 9 नवंबर, 2023 तक गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र 80 स्वर्ण, 69 रजत और 79 कांस्य सहित 228 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि सर्विसेस 66 स्वर्ण, 27 रजत और 33 कांस्य सहित 126 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
- 37वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने पिछले वर्ष गुजरात में खेले गए 36वें राष्ट्रीय खेलों के मुकाबले 26 पदक अधिक जीते मगर द्वितीय स्थान पाने में हरियाणा चार पदकों से चुक गया।
- महाराष्ट्र ने नेशनल गेम्स 2023 मेडल टैली में शीर्ष स्थान प्राप्त करते हुए राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी जीती, जो नेशनल गेम्स में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम को दी जाती है।
- 37वें नेशनल गेम्स में ओलंपिक तैराक श्रीहरि नटराज (8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य) को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट, जबकि जिमनास्ट संयुक्ता प्रसेन काले और प्रणति नायक (4 स्वर्ण और 1 रजत प्रत्येक) को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट चुना गया।
- हरियाणा के जिमनास्टिक खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय खेलों में पहली बार 11 पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। हरियाणा जिमनास्ट ने 4 स्वर्ण, 3 रजत, 4 कांस्य पदक जीतने में कामयाब रहे।
- हरियाणा के कुश्ती खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय खेल में अपने प्रदेश के लिए सर्वाधिक 24 पदक जीते। इनमें 11 स्वर्ण, 1 रजत और 12 कांस्य पदक शामिल हैं।
- टीम स्पर्धा में हरियाणा का प्रदर्शन
  - टीम स्पर्धा में प्रदेश की हॉकी टीमों का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण और महिला टीम ने रजत पदक जीता। पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल मुकाबले में कर्नाटका टीम को 5-3 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला हॉकी टीम का फाइनल मुकाबला मध्य प्रदेश के साथ हुआ। इस मुकाबले में शूटआउट में हार के साथ हरियाणा को रजत पदक पर संतोष करना पड़ा।
  - कबड्डी तथा हैंडबाल स्पर्धा में पुरुष-महिला टीमों को फाइनल में हार के साथ रजत पदक हासिल हुए। वहीं फुटबाल में महिला टीम ने पश्चिम बंगाल को 1-0 से हराकर कांस्य जीतने में काम रही।

अब ज़िलास्तर पर खुलेंगे चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 डेस्क

चर्चा में क्यों ?

13 नवंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब ज़िलास्तर पर जल्द ही चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 डेस्क खुलेंगे। इसकी प्रक्रिया महिला एवं बाल विकास विभाग ने शुरू कर दी है।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेशभर में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के लिये कोई अलग से ज़िलास्तर पर हेल्प डेस्क नहीं है। चाइल्ड हेल्पलाइन पर मदद के लिये आने वाली शिकायतें पंचकूला मुख्यालय के नोडल हेल्प डेस्क पर जाती हैं, जिन्हें वहां से ही संबंधित ज़िलों के बाल संरक्षण अधिकारी के समक्ष कार्रवाई के लिये भेजा जाता है।
- इस प्रक्रिया में न केवल कई बार देरी हो जाती है, बल्कि बाल संरक्षण अधिकारी के पास पर्याप्त स्टाफ नहीं होने की वजह से ज्यादातर शिकायतों पर समय रहते कदम उठाना भी संभव नहीं हो पाता है। इसी के चलते अब महिला एवं बाल विकास विभाग ने ज़िला मुख्यालयों पर जल्द ही अलग से चाइल्ड लाइन हेल्प डेस्क बनाने का निर्णय लिया है।
- पहले चाइल्ड हेल्पलाइन का संचालन एनजीओ के माध्यम से किया जाता था, मगर अब विभाग ने खुद इसे अपने हाथों में लिया है। अब महिला एवं बाल विकास विभाग खुद ही ज़िला मुख्यालयों पर चाइल्ड हेल्पलाइनों का संचालन करेगा। ज़िलास्तर पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 डेस्क खुलने से बच्चों से जुड़ी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई संभव होगी।

- चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क पर पंचकूला मुख्यालय के बजाय ज़िला मुख्यालय पर ही बच्चों की मदद की कॉल जाएंगी। जिन पर तत्परता से अधिकारी संज्ञान ले सकेंगे और बच्चों के राहत एवं बचाव के साथ उन्हें उस मुसीबत से निकालने के लिये तत्परता से प्रभावी कदम उठा सकेंगे।
- ज़िलास्तर पर चाइल्ड हेल्पलाइन में नए स्टाफ की अलग से नियुक्ति भी की जाएगी। इसमें चाइल्ड हेल्पलाइन की कमान ज़िला कोऑर्डिनेटर के हाथों में होगी। वहीं इसमें काउंसलर सहित दस पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जाएगी।
- बाल अपराध से जुड़े मामलों की तहकीकात और बाल यौन शोषण मामलों के लिये प्रत्येक पुलिस थाना में चाइल्ड वेलफेयर पुलिस अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। सीडब्ल्यूपीओ बाल अपराध से जुड़े मामलों में बाल संरक्षण अधिकारी के साथ मिलकर भी काम करते हैं।

जूनियर महिला हॉकी विश्वकपः सोनीपत की तीन महिला खिलाड़ियों का भारतीय टीम में हुआ चयन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चिली की राजधानी सैंटियागो में 29 नवंबर से 10 दिसंबर तक होने वाली एफआईएच विश्व जूनियर महिला हॉकी कप के लिये टीम इंडिया द्वारा घोषित भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में सोनीपत की तीन महिला खिलाड़ियों प्रीति, साक्षी राणा और मंजू चौरसिया का चयन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- विदित हो कि जापान के काकामिगाहारा में 2 से 11 जून तक आयोजित जूनियर महिला हॉकी एशिया कप में भारतीय टीम का नेतृत्व करते हुए प्रीति ने देश की झोली में एशिया कप का खिताब डाला था।
- एशिया कप जीतने के साथ ही भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने जूनियर महिला हॉकी विश्वकप के लिये क्वालिफाई कर लिया था।
- सोनीपत के भगत सिंह कॉलोनी निवासी प्रीति का सफर संघर्ष भरा रहा है। प्रीति 10 साल की उम्र में ही पड़ोस की लड़कियों के साथ ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया स्थित हॉकी मैदान में खेलने जाती थीं।
- ब्रह्म नगर निवासी मंजू चौरसिया ने साल 2010 में हॉकी पर बनी फिल्म चक दे इंडिया देखी। जिसके बाद उन्होंने हॉकी में कुछ कर दिखाने को स्टिक थामी। उनका सपना हॉकी में देश को विश्व कप दिलाना है। अभी वह रेलवे में कार्यरत है।
- उल्लेखनीय है कि जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में टीम इंडिया को पूल सी में जर्मनी, बेल्जियम और कनाडा के साथ रखा गया है। भारतीय टीम का पहला मैच 29 नवंबर को कनाडा के साथ है। इसके बाद भारतीय टीम पहले पूल सी के मुकाबलों में 30 नवंबर व 2 दिसंबर को यूरोपीय टीमों जर्मनी और बेल्जियम से भिड़ेंगी।

राष्ट्रीय बालिका दिवस पर विभिन्न क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाली बालिकाओं को किया जाएगा सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

14 नवंबर, 2023 को हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाली बालिकाओं को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सम्मानित जाएगा। इसके लिये आवेदन की तिथि को एक नवंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कुल 86 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें से 11-11 हजार के 47 पुरस्कार व 39 पुरस्कार राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए दिए जाएंगे।
- प्रवक्ता ने बताया कि सराहनीय कार्य करने वाली बालिकाएं संबंधित ज़िले के महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय में 30 नवंबर तक आवेदन जमा करवा सकती हैं।
- विभाग द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित किये जाने वाले राष्ट्रीय बालिका दिवस के संबंध में जारी निर्देशानुसार किसी भी बालिका द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे- खेलकूद के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई स्थान प्राप्त किया हो, सांस्कृतिक गतिविधियों में राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई स्थान प्राप्त किया हो, समाज सेवा, मीडिया एवं साहित्य एवं खेल के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाली व बहादुरी के क्षेत्र में राज्य द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर नाम भेजा गया हो आदि को पुरस्कार दिया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त 60 प्रतिशत या उससे अधिक विशेष दिव्यांग बच्चों द्वारा सराहनीय कार्य किया गया हो एवं चाइल्ड केयर संस्थान में रह रहे बच्चों ने इन क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किया हो, उन बालिकाओं को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।

सहकारिता मंत्री ने की करनाल शुगर मिल के 48वें पिराई सत्र की शुरुआत

चर्चा में क्यों ?

14 नवंबर, 2023 को हरियाणा के सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने करनाल शुगर मिल मशीन में गन्ने डालकर 48वें पिराई सीजन की शुरुआत की। उन्होंने पिराई सत्र में सबसे पहले गन्ना लाने वाले इन किसानों को सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि इस चीनी मिल में 55 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई के साथ 10% चीनी रिकवरी का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार किसान का एक-एक गन्ना खरीदेगी और समय से पेमेंट भी देगी।
- उन्होंने कहा कि सरकार ने 14 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का दाम बढ़ाकर 386 रुपए देने का काम किया है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। इसके अलावा अगले साल के पिराई सीजन के लिये गन्ने के दाम 400 रुपए प्रति क्विंटल करने की पहले ही घोषणा कर दी गई है।
- डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि शुगर मिलों की क्षमता बढ़ाने का कार्य किया गया है। अब किसानों का गन्ना दूसरे प्रदेश में नहीं जाता। शुगर मिलों में चीनी के साथ-साथ एथनॉल प्लांट व बायोगैस प्लांट भी शुरू किये गए हैं। सहकारी समितियों में काफी सुधार किये गए हैं। पैक्स के कंप्यूटराइज़्ड होने से लोगों को लाभ मिलेगा।

नोट :

9वाँ भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव-2023

चर्चा में क्यों?

15 नवंबर, 2023 को भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (आईआईएसएफ) 2023 का 9वाँ संस्करण 17 से 20 जनवरी, 2024 तक हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- भारत का मेगा विज्ञान मेला फरीदाबाद में ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (टीएचएसटीआई) और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (आरसीबी) के परिसर में आयोजित किया जाएगा।
- वर्तमान संस्करण की विषय वस्तु 'अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क' है।
- आईआईएसएफ 2023 का उद्देश्य व्यापक स्तर पर लोगों को प्रेरित करना और छात्रों, शिक्षकों, वैज्ञानिकों, शोधकर्त्ताओं, उद्योग के पेशेवरों, उद्यमियों तथा विज्ञान संप्रेषकों जैसे विविध स्तर के हितों वाले व्यक्तियों के लिये एक मंच प्रदान करना है।
- आईआईएसएफ 2023 में प्रतिभागियों और आम जनता को विभिन्न लाभ प्रदान करने वाली वैज्ञानिक उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिये कुल 17 विषयवस्तु हैं।यह कार्यक्रम विभिन्न कार्यकलापों जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा संगोष्ठी, वक्ताओं के साथ परस्पर बातचीत, प्रदर्शनियों, प्रतियोगिताओं, कार्यशालाओं, ज्ञान-साझाकरण गतिविधियों, प्रौद्योगिकी शो आदि के माध्यम से सभी हितधारकों के बीच संयोजन रखता है।
- उल्लेखनीय है कि समृद्ध भारत की उन्नति हेतु विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेषण में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिये समर्पित यह कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से विज्ञान भारती के सहयोग से आरंभ किया गया था।
- 2015 से आईआईएसएफ ने भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में आठ संस्करणों का आयोजन किया है और एक विशाल विज्ञान महोत्सव के रूप में विस्तार किया है। 2021 में अंतरिक्ष विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग आईआईएसएफ का अभिन्न अंग बन गए।

ध्यानचंद अवार्डी सज्जन सिंह का निधन

चर्चा में क्यों ?

18 नवंबर, 2023 को चरखी दादरी ज़िला के समसपुर निवासी एवं ध्यानचंद अवार्डी पहलवान सज्जन सिंह फौगाट का लगभग 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

प्रमुख बिंदु

- ध्यानचंद अवार्डी सज्जन सिंह का जन्म 28 जुलाई, 1933 को हुआ था और 1951 में वे सिपाही के पद पर सेना में भर्ती हो गए। स्कूली समय में वो कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी रहे। लेकिन सेना में भर्ती होने के बाद उन्होंने कुश्ती को अपनाया।
- सज्जन सिंह ने कई अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 1960 में रोम ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए सातवां स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार इंडोनेशिया में 1962 में एशियन गेम्स में उन्होंने दो रजत पदक, 1966 के एशियन गेम्स में कांस्य, 1970 के राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक प्राप्त किया।
- उन्होंने 1965, 1967 व 1970 में वर्ल्ड रेसलिंग में देश का प्रतिनिधित्व भी किया। वर्ष 1979 में कटक में उन्हें 'रूस्तमे हिंद'का खिताब हासिल हुआ और 1973 में उन्होंने सेना से सेवानिवृति ली।
- सज्जन सिंह ने वर्ष 1979 में कुश्ती को अलविदा कहा और 1989 में वे साई के कोच बने। सज्जन सिंह को 13 नवंबर, 2021 को तात्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों से ध्यानचंद अवार्ड प्राप्त हुआ था।

भारतीय तकनीक से सुधरेगी 34 देशों की मिट्टी-पानी की गुणवत्ता

चर्चा में क्यों ?

20 नवंबर, 2023 को करनाल स्थित केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान (सीएसएसआरआई) के निदेशक डॉ. आरके यादव ने बताया कि संस्थान की ओर से विकसित तकनीक, प्रौद्योगिकी और लवण सहनशील फसलों की किस्मों से 34 देश अपनी भूमि और भूमिगत जल की गुणवत्ता सुधारेंगे।

प्रमुख बिंदु

- सीएसएसआरआई द्वारा विकसित ये भारतीय तकनीक अब तक 25 देशों तक पहुँच चुकी है, और अभी सात और देशों को तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- विदित हो कि भारत में लगभग 67.4 लाख हेक्टेयर भूमि लवणता और क्षारीय से प्रभावित है, वहीं 34 अफ्रीकी एवं एशियाई देशों में लाखों हेक्टेयर भूमि और भूमिगत जल में लवणता और क्षारीयता बढ़ रही है, जिससे यहाँ की भूमि भी बंजर होने की ओर अग्रसर है।
- अंतर्राष्ट्रीय संस्था अफ्रीकी-एशियाई ग्रामीण विकास संगठन (एएआरडीओ) यानी आरडू ने अपने सभी 34 सदस्य देशों को लवण एवं क्षारीयता प्रभावित भूमि व भूमिगत निम्न गुणवत्ता वाले जल के सुधार के लिये करनाल स्थित सीएसएसआरआई की ओर से विकसित भूमि एवं जल सुधार तकनीक का प्रशिक्षण दिलाने का अनुबंध किया है।
- ये प्रशिक्षण पिछले 13 सालों से चल रहा है। अब तक 25 देशों के 100 वैज्ञानिकों, कृषि विशेषज्ञों को इस तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- सीएसएसआरआई करनाल के निदेशक डॉ. आरके यादव ने बताया कि हाल ही में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये सात देशों (बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरीशस, केन्या, जाम्बिया, जॉर्डन और एस्वातिनी शामिल) से नौ विदेशी वैज्ञानिक व कृषि विशेषज्ञ अधिकारी संस्थान में पहुँचे हैं, जिन्हें तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- सीएसएसआरआई करनाल की ओर से विकसित तकनीकों में क्षारीय भूमि के सुधार के लिये जिप्सम, सल्फर, एफजीडी जिप्सम तकनीक है तो लवणीय भूमि के सुधार के लिये सब सरफेस ड्रेनेज, ड्रेनज तकनीक और लवण सहनसील फसलों की किस्में, उनके बीज हैं तो निम्न गुणवत्ता वाले जल के सुधार के लिये जिप्सम बेड, जिप्सम ब्रेकेट्स व रैपिड एसिडूलेरिंग मैटेरियल और कल्चर आदि कई तकनीक, प्रौद्योगिकी व विधियाँ शामिल हैं।

केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान
CSSRI
1969

नोट :

हकृवि के 10 विद्यार्थियों का पौलेंड के वारसॉ विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण के लिये हुआ चयन

चर्चा में क्यों ?

20 नवंबर, 2023 को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के प्रवक्ता ने बताया कि विश्वविद्यालय के 10 विद्यार्थियों का पौलेंड के वारसॉ विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण के लिये चयन हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि ये विद्यार्थी पौलेंड के वारसॉ विश्वविद्यालय में कृषि, गृह विज्ञान और मत्स्य विज्ञान के क्षेत्रों में नवीन प्रौद्योगिकियों, नवाचारों आदि बारे व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे।
- उपरोक्त विद्यार्थियों का चयन राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (एनएएचईपी-आईडीपी) के तहत अंतर्राष्ट्रीय संगठन में छात्र विकास कार्यक्रम की प्रक्रिया के अंतर्गत परीक्षा और साक्षात्कार आधार पर हुआ है।
- इन चयनित विद्यार्थियों में कृषि महाविद्यालय, हिसार के तृतीय वर्ष के छात्र सुशांत नागपाल, चतुर्थ वर्ष की छात्रा निधि व विशाल, कृषि महाविद्यालय, बावल से मुनीश व नैनसी, कृषि महाविद्यालय कौल से हरितिमा व अंजू, सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय से ममता व मुस्कान और मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय से अमित शामिल हैं।
- विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज ने कहा कि अब तक चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि हिसार विश्वविद्यालय के अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षा व प्रशिक्षणों के लिये विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में जा चुके हैं।

'मिशन हरियाणा कर्मयोगी' के तहत नैतिक व्यवहार मुख्य प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आरंभ

चर्चा में क्यों ?

20 नवंबर, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विडियो संदेश के माध्यम से हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान गुरुग्राम व इसी संस्थान के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र पंचकुला में 'मिशन हरियाणा कर्मयोगी' के तहत मास्टर ट्रेनरों के प्रशिक्षण का शुभांरभ किया।

प्रमुख बिंदु

- ये मास्टर ट्रेनर सरकारी कर्मचारियों में सेवा-भाव और नैतिक व्यवहार को मज़बूत करने का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तथा इसके बाद अपने-अपने ज़िले में लगभग 3.3 लाख सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।
- मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विडियो संदेश के माध्यम से कहा कि हरियाणा अपने कर्मियों के लिये कर्मयोगी मिशन को प्रारंभ करने वाला पहला राज्य है।
- इस अवसर पर हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने भी विडियो संदेश के माध्यम से कहा कि यह नैतिकता प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक अग्रणी कार्यक्रम हैं जिसके तहत प्रदेश के सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने जा रहे हैं।
- हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान की महानिदेशक चंद्रलेखा मुखर्जी ने कहा कि मिशन कर्मयोगी हरियाणा, राज्य सरकार के नैतिक प्रशिक्षण की एक अनुठी पहल है इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों में सेवाभाव और नैतिक व्यवहार जागृत करने के लिये हरियाणा प्रदेश के लभगभ 3.3 कर्मियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है।
- इस कार्य को पूर्ण करने के लिये प्रथम चरण में लगभग 3 हज़ार मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण आरंभ हुआ है। यह प्रशिक्षण समूह में दिया जाएगा और एक समूह में 150 मास्टर ट्रेनर भाग लेंगे, जिनको आगे 30-30 के पांच उप-समूहों में बांटा गया है।
- इस प्रकार 3 उप-समूहों के लिये हरियाणा पुलिस अकादमी में, एक उप-समूह के लिये हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान गुरुग्राम में तथा एक समूह को संस्थान के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र पंचकुला में दो-दो दिन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। द्वितीय चरण में ये सभी मास्टर ट्रेनर जोड़ी बनाकर आगे 30-30 के समूह में 300 कर्मचारियों को नैतिक व्यवहार जागृति का प्रशिक्षण देंगे।

चालू वित्त वर्ष में हरियाणा में अब तक 1.62 लाख टन मत्स्य उत्पादन

चर्चा में क्यों ?

21 नवंबर, 2023 को विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया-2023 में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जय प्रकाश दलाल ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में अब तक राज्य में 46,493 एकड़ जलक्षेत्र में 1.62 लाख टन मत्स्य उत्पादन हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- जेपी दलाल ने हरियाणा सरकार द्वारा मत्स्य पालन के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिये किसानों को जागरूक करने के साथ-साथ नई-नई योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं।
- अगले पाँच वर्षों में राज्य सरकार ने अतिरिक्त 15,000 एकड़ में लगभग 30,000 टन झींगा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में अब तक राज्य में 46,493 एकड़ जलक्षेत्र में 1.62 लाख टन मत्स्य उत्पादन तथा लगभग 4350 एकड़ में 7500 टन झींगा उत्पादन हुआ है, जिससे मत्स्य पालकों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- उन्होंने बताया कि गत वित्त वर्ष में 45,015 एकड़ जलक्षेत्र में 2.12 लाख टन मत्स्य उत्पादन हुआ था।
- विदित हो कि गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया-2023 सम्मेलन में राज्य मत्स्य पालन मंत्रियों, विभिन्न देशों के राजदूतों, वैश्विक मत्स्य वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, मत्स्य समुदायों और निवेश बैंकरों सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों और हितधारकों ने हिस्सा लिया।

आइडियाथॉन हरियाणा 2023 का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

21 नवंबर, 2023 को हरियाणा कौशल विकास मिशन के एमडी डॉ. विवेक अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा हरियाणा के आईटीआई, एचएसडीएम प्रशिक्षण केंद्रों, पॉलिटेक्निक कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों के साथ-साथ आम जनता के बीच उद्यमशीलता और स्टार्टअप विचारों को बढ़ावा देने के लिये आइडियाथॉन हरियाणा 2023 का शुभारंभ किया गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- डॉ. विवेक अग्रवाल ने बताया कि इसके लिये इच्छुक प्रार्थी 1 दिसंबर तक पंजीकरण करवा सकते हैं तथा विचारों को जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर, 2023 निर्धारित की गई है। इसके बाद विजेताओं के लिये पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी।
- इस प्रतियोगिता में वैध परिवार पहचान पत्र आईडी वाले ही भाग ले सकते है। यह एक विशेष ऑनलाइन टेक इवेंट है जिसमें 4 लाख से रुपए अधिक की पुरस्कार राशि हरियाणा के 21 विजेताओं को प्रदान की जाएगी।
- लगातार एक महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत हरियाणा के युवाओं को एक साथ लाने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा हैं। इससे प्रार्थी अपनी रचनात्मकता और कौशल का उपयोग नवीन समाधान खोजने, वैश्विक चुनौतियों का सामना करने और वास्तविक दुनिया की समस्याओं के लिये प्रोटोटाइप या समाधान विकसित करने के लिये अपने विचार दे सकते है।
- उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता की 12 श्रेणियों में प्रतिभागी अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। इनमें कृषि, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उभरती तकनीक, हेल्थटेक, क्लीनटेक, गतिशीलता, शिल्प और स्थिरता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, उपभोक्ता और उद्यम प्रौद्योगिकी और अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण शामिल हैं।
- प्रतिभागी एकल या टीम के रूप में कार्यक्रम के लिये पंजीकरण करवा सकते है और उन्हें अपने विचारों को 5 से अधिक स्लाइडों के पिच डेक और 2 मिनट के वीडियो पिच के साथ जमा करना होगा।

आईआईटीएफ: हरियाणा मंडप में दिखी आधुनिक तकनीक से बनी ई-साइकिल

चर्चा में क्यों?

22 नवंबर, 2023 को हरियाणा के सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा निदेशालय से मिली जानकारी के अनुसार नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (आईआईटीएफ) 2023 में हरियाणा मंडप में आधुनिक तकनीक से बनी ई-साइकिल को भी शामिल किया गया है जो स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण सहेजने में भी मददगार होगी।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा में बने ई-साइकिलिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट अप विकास यादव लेकर आए हैं। विकास इससे पहले जापान की राजधानी टोक्यो में बहुचर्चित कंपनी 'टेस्ला' में नौकरी कर चुके हैं। कोविड महामारी के दौरान उनकी नौकरी चली गई, जिसके बाद भारत लौटकर उन्होंने अपने गृह स्थान हरियाणा के रेवाड़ी में अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया।
- उस समय के हालात और आम जनमानस के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्होंने ई-साइकिल बनाने का निश्चय किया। मेक इन इंडिया के स्लोगन से प्रेरित होकर विकास ने 'मेक इन हरियाणा' को अपना लक्ष्य बनाया।
- उन्होंने पैनासोनिक बैटरी सेल से बैटरी पैक तैयार किया जो ई-साइकिल के लिये परफेक्ट है। यह ई-साइकिल सभी वर्गों को देखते हुए तैयार किया गया है। इस ई-साइकिल में ग्रामीण क्षेत्र में 50 से 60 किलोमीटर जाने के लिये मात्र 3 रुपए का खर्च आता है और वहीं शहरी क्षेत्र में यह खर्च 5 रुपए तक आता है।
- उन्होंने बताया कि यह भारत की पहली साइकिल कंपनी है जिसके पास ई-साइकिल में फ्रंट ड्राइव, मिड ड्राइव और रेयर ड्राइव के विकल्प हैं। विकास ने विदेशों में एक्सपोर्ट के लिये सैंपल कोरिया, नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका में भेजे हैं। उनके इस स्टार्टअप को विदेशों में भी बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है।
- विदित हो कि आईआईटीएफ 2023 में हरियाणा से जुड़े कई ऐसे स्टार्टअप्स को जगह दी गई है जिसमें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से एमएसएमई से जुड़े छोटे व्यवसायियों ने हिस्सा लिया।
- इनका स्टार्ट अप आम आदमी को पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण से निजात दिलाने के साथ ही ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिलाने में भी मददगार साबित होंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में मदद करेगा।

नोट :

दयालु योजना के तहत 1159 लाभार्थियों को दी गई 44.48 करोड़ रुपए की राशि

चर्चा में क्यों ?

23 नवंबर, 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय परिवारों को सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) के तहत 1159 लाभार्थियों को 44.48 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुँचाई।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दुर्घटना में परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने अथवा दिव्यांग हो जाने पर उस परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। गरीब परिवार तो आर्थिक रूप से भी बड़े संकट से घिर जाता है। हमने ऐसे परिवारों की चिंता करते हुए उन्हें आर्थिक मदद पहुँचाने के लिये दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) शुरू की गई है।
- इस योजना के अंतर्गत 1 लाख 80 हज़ार रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार के 6 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत अभी तक 1964 लाभपात्रों को 75 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में डाली गई है।
- इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जा रहा है।
- दयालु योजना के अंतर्गत विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार लाभ दिया गया है। 6 से 12 वर्ष आयु तक के लिये 1 लाख रुपए, 12 से अधिक व 18 वर्ष तक 2 लाख रुपए, 18 से अधिक व 25 वर्ष तक 3 लाख रुपए, 25 से अधिक व 45 वर्ष तक 5 लाख रुपए, 45 से अधिक व 60 वर्ष तक 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है।
- इस लाभ में 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) या विभिन्न विभागों द्वारा संबंधित वर्ग के लिये चलाई जा रही योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि भी शामिल है।

हरियाणा सरकार निकायों के सफाई कर्मचारियों को देगी प्रोत्साहन राशि

चर्चा में क्यों ?

23 नवंबर, 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि भारत सरकार द्वारा कराए जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में उच्चतम 25 प्रतिशत (सबसे अच्छा प्रदर्शन) की श्रेणी में आने वाली निकायों के सफाई कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि उन पालिकाओं के सफाई कर्मचारियों को 12,000 रुपए वार्षिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जो स्वच्छ सर्वेक्षण के प्रदर्शन के आधार पर सभी पालिकाओं में सबसे ऊपर 25 प्रतिशत की श्रेणी में होंगी।
- इसके अतिरिक्त अगली 25 प्रतिशत की श्रेणी में आने वाली पालिकाओं के सफाई कर्मचारियों को भी 9,000 रुपए वार्षिक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि निकायों के सफाई कर्मचारियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि भारत सरकार द्वारा करवाए जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण के प्रदर्शन के आधार पर दी जाएगी।
- किसी एक वर्ष में हुए स्वच्छ सर्वेक्षण के दौरान निकायों के प्रदर्शन के आधार पर अगले वित्त वर्ष में दिये जाने वाले प्रोत्साहन की श्रेणी तय की जाएगी। अगले वर्ष में पुन: नवीनतम सर्वेक्षण के प्रदर्शन के आधार पर आने वाले वर्ष की प्रोत्साहन राशि तय की जाएगी।
- मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह प्रोत्साहन राशि 4 किस्तों में प्रदान की जाएगी। वित्त वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत में एक किस्त दी जाएगी। इससे सफाई कर्मचारियों को सालाना लगभग 20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मिलेगी। इनमें नियमित कर्मचारी, पालिका रोल के कर्मचारी, आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मचारी आदि शामिल हैं।

हरियाणा सरकार ने क्रिटिकल केयर ब्लॉक और डीआईपीएचएल के लिये सीपीडब्ल्यूडी के साथ किये एमओयू पर हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों ?

23 नवंबर, 2023 को हरियाणा सरकार ने राज्य में 15 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 17 ज़िला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (डीआईपीएचएल) के निर्माण के लिये केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना का निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू होगा। अंबाला कैंट में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है और इसका 40 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, जिसके दिसंबर 2024 तक पूरा होने की संभावना है।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. जी. अनुपमा ने कहा कि केंद्र सरकार से सिविल अस्पताल अंबाला कैंट में क्रिटिकल केयर ब्लॉक और ज़िला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला के निर्माण के लिये दूसरी किस्त जारी करने का अनुरोध किया गया है। इस परियोजना के लिये कुल बजट का 90 प्रतिशत 18.92 करोड़ रुपए में से 16.63 करोड़ रुपए का उपयोग किया जा चुका है।
- इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग को राज्य में दो क्रिटिकल केयर ब्लॉक और पाँच ज़िला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के निर्माण का कार्य भी सौंपा गया है।

देश में सैनिक एवं अर्द्धसैनिक कल्याण विभाग गठित करने वाला हरियाणा पहला राज्य

चर्चा में क्यों ?

26 नवंबर, 2023 को हरियाणा के सैनिक एवं अर्द्धसैनिक कल्याण राज्य मंत्री ओमप्रकाश यादव ने कहा कि हरियाणा देश में पहला राज्य है, जहाँ पर सैनिक एवं अर्द्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से पूर्व सैनिकों एवं अर्द्धसैनिकों के कल्याण के लिये अनेक कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा में युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना के जवानों एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों को पहले अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए दी जाती थी, जिसे प्रदेश सरकार ने बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है।
- इसके साथ ही आई.ई.डी. ब्लास्ट के दौरान शहीद होने पर भी 50 लाख रुपए दिये जाते हैं।
- हरियाणा सरकार ने अक्तूबर, 2014 से अब तक शहीद सैन्य/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 367 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान की है।
- 26 नवंबर को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु पंचकूला में संविधान दिवस एवं मिलेट्स डे मनाया गया। इस अवसर पर मिलेट्स से बने प्रोडक्ट भी प्रदर्शित किये गए।
- इस अवसर पर भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु पंचकूला के महानिरीक्षक ए.पी.एस. निम्बाड़िया भी मौजूद रहे।
- गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने 8 राज्य राजमार्गों के सुधार और सिवाहा-पिल्लूखेड़ा रोड के चौड़ीकरण को दी मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

25 नवंबर, 2023 को हरियाणा राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ाने और निर्बाध परिवहन सुविधा की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 75.16 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 8 राज्य राजमार्गों के सुधार के अलावा 1.47 करोड़ की लागत से सिवाहा-पिल्लूखेड़ा सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिये प्रशासनिक मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- 6.80 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट के साथ अंबाला ज़िले में 12.72 किलोमीटर तक फैली जगाधरी-बिलासपुर साढ़ौरा-नारायणगढ़-रायपुर रानी का सड़क सुधार किया जाएगा।
- 1.69 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि के साथ भिवानी ज़िले में बरवाला-हिसार-सिवनी सिंघानी सड़क (एसएच-19) का सुधार किया जाएगा, इस सड़क की लंबाई 5.40 किमी. है।
- 5.38 करोड़ रुपए की लागत से भिवानी ज़िले में 9.23 किलोमीटर तक फैली रेवाड़ी-दाहिना-कनीना-महेंद्रगढ़-सतनाली-लोहारू सड़क (एसएच संख्या-26) का सुधार किया जाएगा।
- 17.72 करोड़ रुपए की लागत से 32.00 किलोमीटर लंबी महेंद्रगढ़ ज़िले में महेंद्रगढ़-सतनाली-लोहारू सड़क (एसएच-24) का सुधार किया जाएगा।
- हिसार ज़िले में 7.62 करोड़ रुपए की लागत से 11.67 किलोमीटर लंबी आदमपुर से झांसल रोड का सुधार शामिल है।
- करीब 27.58 करोड़ रुपए से हिसार ज़िले में 26.038 किलोमीटर लंबी करनाल असंध-जींद-हांसी रोड (एसएच-12) का सुधार किया जाएगा।
- करनाल ज़िले में कुल 3.8 करोड़ रुपए की लागत से 0.500 किलोमीटर लंबी कुंजपुरा करनाल रोड (एसएच-08) पर आरसीसी साइड ड्रेन बनाया जाएगा।
- 7.96 करोड़ रुपए से हिसार ज़िले में 7.064 किलोमीटर लंबी सुरेवाला चौक से उकलाना भूना (एसएच-02) रोड के अलावा 1.47 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सिवाह से पिल्लूखेड़ा रोड का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।

नोट :

कैंसर रोग की 'थर्ड एवं फोर्थ स्टेज' के मरीजों को मिलेगी वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के समान वित्तीय सहायता

चर्चा में क्यों ?

27 नवंबर, 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कैंसर रोग की 'थर्ड एवं फोर्थ स्टेज' के मरीजों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर मासिक वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई। यह योजना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता आवेदक द्वारा किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्राप्त किये जा रहे लाभ के अतिरिक्त होगी।
- इस योजना के तहत पात्र कैंसर रोगियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर 1 जनवरी, 2024 से 3000 रुपए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- ऐसे कैंसर के मरीज, जिनकी पारिवारिक सालाना आय अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि को छोड़कर 3 लाख रुपए से कम है, वे इसके पात्र होंगे।
- इस योजना का उद्देश्य कैंसर की 'थर्ड एवं फोर्थ स्टेज' के मरीजों के सामने आने वाले वित्तीय बोझ को कम करना है। यह योजना हरियाणा राज्य में सभी आयु वर्ग के चरण-3 व 4 कैंसर रोगियों के लिये लागू होगी।
- इसके तहत कैंसर के गंभीर रोगियों की आवश्यकता, जीवनयापन के खर्चों, बुनियादी ज़रूरतों, चिकित्सा व्यय, अप्रत्यक्ष लागत, ओओपीई आदि के लिये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- योजना के तहत रोगी की पात्रता में 'बोनफाइएड-रेजिडेंस' की शर्तें मान्य होंगी। इसके अलावा, आवेदक के पास परिवार पहचान-पत्र भी होना चाहिए।
- विदित हो कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 9 मई, 2022 को अटल कैंसर सेंटर अंबाला कैंट के उद्घाटन के दौरान कैंसर के तीसरे एवं चौथे चरण के रोगियों के लिये पेंशन की घोषणा की थी।
- उल्लेखनीय है कि कैंसर एक बहुक्रियात्मक बीमारी है, जो भारत में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। भारत में प्रतिवर्ष 13.24 लाख नए कैंसर के मामले और लगभग 8.51 लाख कैंसर से संबंधित मौतें दर्ज की जाती हैं। हरियाणा में वर्ष 2020 में अनुमानित 29,000 नए कैंसर के मामले और 16,000 कैंसर से मौतें हुई हैं।
- कैंसर के तीसरे एवं चौथे चरण में करीब 64 प्रतिशत मरीज गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना को मंज़ूरी मिलने से कैंसर रोग की 'थर्ड एवं फोर्थ स्टेज' के मरीजों को वित्तीय सहायता मिलने से काफी राहत मिलेगी।

नोट :

बकाया राशि की वसूली के लिये 'हरियाणा एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम 2023' को मिली मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

27 नवंबर, 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हरियाणा में बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने और मुकदमेबाजी कम करने के उद्देश्य से 'एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम 2023' नामक एक अनूठी योजना को मंज़ूरी प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा करते हुए कहा था कि बकाया वसूली के लिये विवादों का समाधान योजना के तहत इस प्रकार की एक योजना लाई जाएगी।
- यह योजना पूर्व-जीएसटी प्रणाली में आबकारी एवं कराधान विभाग के विभिन्न अधिनियमों द्वारा शासित बकाया राशि की वसूली की सुविधा के लिये बनाई गई है। यह योजना अधिसूचना की तिथि से लागू होगी।
- इस योजना के अंतर्गत आने वाले अधिनियमों में सात अधिनियमों नामत: हरियाणा मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2003, केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम 2000, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2008, हरियाणा सुख साधन कर अधिनियम 2007, पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम 1955 और हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम 1973 से संबंधित बकाया शामिल हैं।

हरियाणा मंत्रिमंडल ने संचार और कनेक्टिविटी अवसंरचना नीति में संशोधन को दी मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

27 नवंबर, 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पूरे राज्य में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिये उच्च गुणवत्ता वाली प्रौद्योगिकी और संचार बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से 'कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी-2023' में संशोधन को मंज़ूरी दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- यह नई पॉलिसी 'कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी-2017' की जगह लेगी और 2022 में केंद्रीय संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) द्वारा अधिसूचित संशोधित भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे नियमों के साथ संरेखित होगी।
- कैबिनेट का यह निर्णय दूरसंचार क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकी प्रगति के एकीकरण को प्रोत्साहित करता है, जिसमें 'फाइबर टू द होम' (एफटीटीएच) और 'ओपन एक्सेस नेटवर्क' (ओएएन) जैसे अभिनव व्यवसाय मॉडल शामिल हैं, जो नेटवर्क तक भौतिक पहुँच को सेवा वितरण से अलग करता है।
- यह संशोधित नीति सड़कों के किनारे नलिकाओं के माध्यम से 5जी सक्षम बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिये एक रूपरेखा स्थापित करती है, जिससे कई सेवा प्रदाताओं को 'राइट ऑफ वे' (आरओडब्ल्यू) उपलब्धता को अनुकूलित करने और कई बुनियादी ढाँचे प्रदाताओं द्वारा आरओडब्ल्यू में खुदाई के कारण होने वाले बार-बार होने वाले व्यवधानों को रोकने के लिये एक ही बुनियादी ढाँचे को साझा करने की अनुमति मिलती है।
- नए स्वीकृत कार्यक्रम के तहत, यदि नोडल अधिकारी आवेदन जमा करने की तारीख से 45 दिनों के भीतर अनुमति देने या आवेदन को अस्वीकार करने में विफल रहता है, तो अनुमति दी गई मानी जाएगी। संबंधित ज़िले के उपायुक्त सभी मंज़ूरियों के लिये एकमात्र संपर्क व्यक्ति होंगे।
- भारत सरकार के दूरसंचार विभाग से पंजीकृत या लाइसेंस प्राप्त कोई भी दूरसंचार बुनियादी ढाँचा और सेवा प्रदाता या संचार और कनेक्टिविटी बुनियादी ढाँचे को बिछाने के लिये लाइसेंस धारी द्वारा विधिवत अधिकृत बुनियादी ढाँचा प्रदाता इस नीति के तहत राज्य में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर एवं संचार स्थापित करने, बिछाने या प्रदान करने के लिये अनुमति लेने के लिये पात्र है।

नोट :

पानीपत रिफाइनरी के विस्तार के लिये तीन गाँवों की ग्राम पंचायतों को ज़मीन बेचने की मंज़ूरी मिली

चर्चा में क्यों ?

27 नवंबर, 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आईओसीएल पानीपत रिफाइनरी के पहले चरण के विस्तार के लिये तीन गाँवों की ग्राम पंचायतों को 350.5 एकड़ पंचायती ज़मीन को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पानीपत रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स पानीपत को बेचने की मंज़ूरी प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

- आईओसीएल, पानीपत रिफाइनरी आसन कलाँ गाँव की 140 एकड़ 6 कनाल 12 मरला, बाल जाटान गाँव की 152 एकड़ 2 कनाल 15 मरला व खंडरा गाँव की 57 एकड़ 2 कनाल 19 मरला भूमि को बाज़ार कीमत 2.20 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की दर से खरीदेगी।
- इसके अलावा, आईओसीएल इन गाँवों के विकास कार्यों के लिये ग्राम पंचायतों को 10 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से राशि का भी भुगतान करेगी।
- गौरतलब है कि राज्य के स्वामित्व वाली तेल दिग्गज कंपनी ने 4,200 एकड़ से अधिक क्षेत्र में पानीपत में अपनी पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की है।
- आईओसीएल ने रिफाइनरी के विस्तार के लिये हरियाणा सरकार से करीब 600 एकड़ ज़मीन देने का अनुरोध किया था, जिसमें से 349 एकड़ ज़मीन सरकार ने उपलब्ध करा दी है।

राज्य की पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-ए की 7 जातियाँ हरियाणा अनुसूचित जाति वर्ग सूची में शामिल

चर्चा में क्यों ?

27 नवंबर, 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हरियाणा राज्य की पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-ए में क्रम संख्या-1 से 7 जातियों नामत: अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरि, तुरी या थोरी को हटाकर हरियाणा अनुसूचित जाति वर्ग सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इसके अलावा, हरियाणा पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-ए सूची में क्रम संख्या 50 पर उल्लेखित 'राय सिख' जाति को भी हटाया गया है और इसे भी हरियाणा अनुसूचित जाति वर्ग सूची में शामिल किया गया है।
- हरियाणा सरकार के इस निर्णय से अब इन जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग का लाभ मिलेगा।
- इसके साथ ही हरियाणा पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-ए सूची में क्रम संख्या 31 पर 'जंगम-जोगी' जाति शब्द को संशोधित कर 'जंगम' कर दिया गया है।
- हरियाणा सरकार की ओर से अनुसूचित जाति आयोग राज्य के 'नायक' समुदाय को अनुसूचित जाति वर्ग की सूची में शामिल करने के लिये केंद्र सरकार को लिखित पत्र भेजा जाएगा। भारत सरकार के निर्देशानुसार इस संबंध में आगे की कार्यवाही की जाएगी।

सरकार ने 32.69 करोड़ रुपए की 14 नई परियोजनाओं को दी मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

28 नवंबर, 2023 को हरियाणा सरकार ने प्रदेश की ग्रामीण आबादी के जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के प्रयास में 2 ज़िलों फतेहाबाद और हिसार में संवर्द्धन ग्रामीण जल आपूर्ति-राज्य योजना के तहत 32.69 करोड़ रुपए से अधिक की 14 नई परियोजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- 'ऑग्मेंटेशन रूरल वाटर सप्लाई-स्टेट प्लान' के तहत नए कार्यों में ज़िला हिसार के नारनौंद कस्बे के एमसी क्षेत्र में 4.23 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से शेष सीवर लाइनें बिछाना शामिल है।
- इसके अलावा ज़िला फतेहाबाद के गाँव बलियाला और बोरा में नहर आधारित जल कार्य बलियाला का निर्माण की अनुमानित लागत 7.23 करोड़, गाँव करांडी तहसील टोहाना ज़िला की विभिन्न गलियों में 23.32 लाख रुपए की अनुमानित लागत से डीआई जल आपूर्ति पाइपलाइन बिछाया जाएगा।
- फतेहाबाद ज़िला के गाँव मढ़ में स्वतंत्र नहर आधारित जल निर्माण कार्य का निर्माण 3.93 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से, गाँव नांगल में 1.04 करोड़ रुपए की लागत से जलापूर्ति योजना का विस्तार, गाँव दुलत में 24.35 लाख रुपए की अनुमानित लागत से डीआई जल आपूर्ति पाइपलाइन बिछाना, गाँव रत्ताखेड़ा में 1.54 करोड़ रुपए की लागत से जलापूर्ति योजना का विस्तार किया जाएगा।
- फतेहाबाद ज़िला के ही गाँव अलावलवास में मौजूदा वितरण प्रणाली का प्रतिस्थापन और जल कार्य संरचनाओं की मरम्मत पर 2.77 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से, गाँव बीरबाड़ी में 3.17 करोड़ की लागत से स्वतंत्र नहर आधारित जल कार्य प्रदान करना, गाँव बुवान में 1.86 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से जल आपूर्ति योजना में सुनिश्चित कच्चे पानी के लिये एक संप वेल का निर्माण किया जाएगा।
- इसके अलावा राइजिंग मेन उपलब्ध कराने और बिछाने, दादूपुर ढ़ाणी के लिये 1.83 करोड़ रुपए की लागत से एक अतिरिक्त बूस्टिंग स्टेशन, राइजिंग मेन का निर्माण और 1.11 करोड़ रुपए की लागत से गाँव दरियापुर में जल कार्यों की मौजूदा संरचना की मरम्मत, ग्राम गादली में 1.34 करोड़ रुपए की लागत से जल आपूर्ति योजना का आधुनिकीकरण तथा गाँव जंडली खुर्द में 2.11 करोड़ रुपए की लागत से जल आपूर्ति योजना का विस्तार और बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण, जल कार्य संरचनाओं की मरम्मत की जाएगी।

हरियाणा एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद करने वाला बना देश का पहला राज्य

चर्चा में क्यों?

28 नवंबर, 2023 को हरियाणा एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार द्वारा गन्ने के प्रति क्विंटल दाम 372 रुपए से बढ़ाकर 386 रुपए कर दिया गया है, जो कि देश में सबसे अधिक है। इसके साथ ही सरकार ने गन्ना किसानों की भविष्य की भी सुध लेते हुए आगामी वर्ष के लिये भी दाम 400 रुपए प्रति क्विंटल देने की घोषणा की है।
- प्रदेश सरकार द्वारा मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल के तहत पिछले 7 सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में 85,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 29.45 लाख किसानों को 7656 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम किया है।
- किसानों को फसल बेचने में असुविधा न हो, इसके लिये प्रदेश सरकार द्वारा गन्नौर, सोनीपत में 7,000 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉर्टिकल्चर मार्केट का निर्माण करा रही है।
- इसी तरह से प्रदेश सरकार पिंजौर में 150 करोड़ रुपए की लागत से सेब, फल और सब्जी मंडी का निर्माण करा रही है। इसके साथ ही सरकार ने नई व अतिरिक्त मंडियों के विकास पर 1074 करोड़ रुपए खर्च किये हैं।
- 1,74,464 एकड़ धान की खेती की जगह वैकल्पिक फसलों की खेती कराई जा रही है। इसी के तहत प्रदेश सरकार ने 7000 रुपए प्रति एकड़ की दर से 118 करोड़ रुपए की किसानों को सहायता प्रदान की है। साथ ही सरकार ने भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरा उत्पादन करने वाले किसानों के खाते में 836 करोड़ रुपए भेजी है।
- प्राकृतिक खेती योजना के तहत 11,043 किसानों को पंजीकृत किया गया है। उनको प्रशिक्षण देने के लिये गुरुकुल कुरुक्षेत्र, हमेटी (जींद), मंगियाना (सिरसा) और घरौंडा में प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केंद्र शुरू किये गए हैं।
- राज्य सरकार ने अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना के माध्यम से 10 रुपए प्रति थाली भोजन उपलब्ध करवाने के लिये 25 मंडियों में कैंटीन शुरू की है। राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल (ई-नाम) से राज्य की 108 मंडियों को जोड़ा गया है। साथ ही पंचकूला, सेक्टर-20 और गुरुग्राम में किसान बाजार शुरू किया गया है।
- सरकार ने पराली प्रबंधन पर होने वाली खर्च की पूर्ति के लिये प्रति एकड़ की दर से किसान को 1000 रुपए अनुदान दे रही है।

नोट :